Research Inspiration
An International Multidisciplinary-Journal
ISSN: 2455-443X Journal home page: www.researchinspiration.com
Vol. 07, Issue-I, Dec. 2021

मध्य प्रदेश में संचालित ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं का विकास में योगदान
(Contribution to the development of rural sector schemes operated in Madhya Pradesh)

Chetna Garg[a,*]

[a] *Research Scholar (Sociology), Govt. Kamla Raja Girls P.G. College, Jiwaji University, Gwalior, Madhya Pradesh (India).*

KEYWORDS

ग्रामीण क्षेत्रों की योजनायें, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, योजनाओं का समाज पर प्रभाव, ग्रामीण समाज में योजनाओं की आवश्यकता

ABSTRACT

राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में विकास की एक नई लहर देखी जाती हैं। अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की हमेशा कमी रहती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि गॉवों में संसाधनों की कमी के कारण वहां पर रोजगार आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और ना ही कोई बड़े कारखाने होते हैं। जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके और ना ही लोगों के पास इतना धन होता है कि जिससे वह स्वरोजगार की शुरूआत कर सकें या अपना स्वयं का कोई उद्योग लगा सके। अब ऐसी परिस्थियों में एक ही उपाय बचता है कि राज्य शासन इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये या कुछ योजनाएं चलाएं जिससे वहॉ के लोगों को रोजगार मिल सके। और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनायें संचालित की जा रही है। जिनसे आम–जन को जिनके पास घर नही है उनको आवास योजना का लाभ मिल सके और जिनके कच्चे मकान है उनको पक्के मकान बनाने के लिए धनराशि दिलायी जाती है। जो बीमार है उनके लिए चिकित्सा योजनायें चलाई जा रही है। और शैक्षिणक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस शोध पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का मूल्यॉकन करना है और इन योजनाओं के लाभ से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास का समीक्षात्मक अध्ययन करना है।

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं से समाज को अत्यधिक रूप से लाभ भी मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के कारण ही आज का युवा वर्ग अपने रोजगार को पाने में सक्षम हो रहा है। जिनको उपचार की आवश्यकता है उनको उपचार भी मिल रहा है। शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की वयवस्था है और यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करवाना चाहता है तो प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के आधार पर निःशुल्क उपचार शासन द्वारा करवाया जाता है। इसमें कुछ योजनाएं जो कि कैरियर मार्गदर्शन से संबंधित हैं उनमें भी विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ प्राध्यापकों की ड्यूटी लगा कर के समाज को उचित मार्गदर्शन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गॉव के ही कुछ युवा लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर उनको सुविधा मुहैया कराई जाती है। कुछ लोगों की जिनकी संड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है या फिर उनको कोई चोट लग जाती है इसके लिए विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश स्तर पर मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015। यदि छोटे बच्चों की बात करें तो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा छोटे बच्चें जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं उनके कुपोषण को दूर करने के लिए भी पोषण से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजना संचालित की जाती है। महिलाओं के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं जिसमें महिलाओं को सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने के दौरान भी उनको कुछ धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। सबसे बड़ा कदम भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लड़कियों के जन्म लेने पर उनके विवाह के लिए अग्रिम धनराशि जमा की जाती है। जिससे उनके परिवार लड़कियों के विवाह की चिंताओं से मुक्त हो जाते है।

मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग

म.प्र. ग्रामीण विकास विभाग गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, ग्रामीण अवसंरचना, निवासियों के विकास, न्यूननतम बुनियादी सेवाओं के प्रावधान आदि के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों का कार्यान्वन कर रहा है। इस बात को ध्यांन में रखते हुए कि ग्रामीण सड़कें गांव में गरीबी उपशमन के लिए आर्थिक विकास और उपायों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों में और सड़क सम्पर्क से वंचित गॉवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है यानि कि हर गॉव तक पक्की सड़कों का निर्माण करना है। वर्तमान में भारत के लगभग सभी गॉवों को पी.एम.जी.एस. वाई. स्कीम से जोड़ा गया है।[1]

मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं

मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार की है–

स्टांप वेंडर योजना

स्टांप वेंडर योजना मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे लोगों के लिए शुरू की गई है जो शिक्षित हैं और बेरोजगार है। उनके लिए राज्य शासन के द्वारा इनको एक लाइसेंस प्रदान किया जाता है। जिससे यह ऑनलाइन स्टांप पेपर शासन की वेबसाइट से जनरेट करके बेच सकते हैं। जितने स्टांप पेपर इनके द्वारा बिक्रय किये जायेगे उसकी कुल कीमत का तीन प्रतिशत कमीशन के रूप में इनको मिलता है जिससे बहुत लोगों को घर बैठे रोजगार मिला है और उनका जीवन यापन होना शुरू हो गया। सरकार द्वारा यह एक अच्छी पहल है।

वसुंधरा योजना

वसुंधरा योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो गरीब हैं और अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित हैं। यदि वह किसी जमीन को जो कृषि भूमि है को खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए बिना ब्याज के ऋण मुहैया कराना इस योजना का लक्ष्य है।

दीनदयाल समर्थ योजना

दीनदयाल समर्थ योजना मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई थी। इसमें उन लोगों को जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त हैं, उनको इस

*** Corresponding author**
E-mail: E-mail: chetnagarg39@gmail.com (Chetna Garg). https://orcid.org/0000-0001-5584-3011
DOI: https://doi.org/10.53724/inspiration/v7n1.04
Received 15th Dec. 2021; Accepted 25nd Dec. 2021
Available online 30th Dec. 2021
2455-443X /© 2021 The Authors. Published by Research Inspiration (Publisher: Welfare Universe). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

योजना के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ–साथ, रोजगार एवं उनके जीवन जीने के लिए हर प्रकार से सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। इस योजना का भी समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना

मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस योजना का शुभारंभ 2004 में किया गया था। इसमें ऐसे लोगों को उपचार प्रदान करने की योजना बनाई गई है। जो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उन परिवारों का इलाज शासन द्वारा शासकीय खर्च पर किया जाता है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

यह योजना भारत शासन द्वारा प्रारंभ की गई एवं इस योजना की एक खास बात है कि जो परिवार गांव में निवास करते हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जहां पर वह परिवार निवास करता है उसी के आसपास रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। हालांकि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाता है। क्योंकि 75 प्रतिशत हिस्सा भारत शासन के द्वारा और वहीं पर राज्य शासन के द्वारा भी 25 प्रतिशत का हिस्सा संयुक्त रूप से खर्च किया जाता है। इस योजना के तहत उन परिवारों को जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है एवं उनकी आय में वृद्धि हो सके इसलिए आवश्यक कदम उठाये जाते है।

स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना

इस योजना का शुभारंभ मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से छात्रों को सही ढंग से कैरियर मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे छात्र–छात्रायें सही समय पर सही कैरियर का चुनाव कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थियों को कृषि संबंधित पाठ्यक्रम और कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न किए जाएं इस उददेश्य से मार्गदर्शन दिया जाता है। जो छात्र–छात्रायें प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पुनर्विवाह योजना प्रस्तावित है इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के द्वारा घोषण की गयी है कि विधवा से विवाह करने पर ₹200000 की राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसमें महिला की अधिकतम आयु 40 वर्ष एवं पुरुष की अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है।[2]

प्रधानमंत्री ग्रामीण अवास योजना

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था। इस योजना के अर्न्तगत केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा सम्मिलित रूप से कार्य किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत 60 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा कुल लागत का खर्चा उठाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का घर बनाने के लिए यह धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। जिससे वह अपने कच्चे घर को पक्के घर में परिवर्तित कर सकें।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अगस्त 2014 में शुरू किया था। यह योजना युवाओं को अपने कारोबार या उद्योग को शुरू करने के लिए ऋण की सुवधा प्रदान करती है। जिससे युवा वर्ग अपने पंसद के उद्योग को शुरू कर सकते है। इस योजना के माध्यम से युवा वर्ग को अपना उद्योग स्थापित करने का प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी नागरिक उठा सकते है।[3]

लाड़ली लक्ष्मी योजना

यह योजना मध्य प्रदेश में अप्रैल 2007 से प्रारम्भ की गई। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाना, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई।[4] इस योजना का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ा है। इसका प्रमुख कारण था कि गरीबी के कारण जिन परिवारों के द्वारा बेटी जन्म को अभिशाप समझा जाता था वही अब इसको वरदान समझने लगे है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों हेतु अन्य योजनायें

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों हेतु विभिन्न प्रकार की अन्य योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिससे जो लोग समाज की मुख्य धारा से दूर है उनकों समाज के साथ मुख्य धारा से जोड़ा जा सकें। ये प्रमुख योजनायें निम्नलिखित है–

जल जीवन योजना, स्वावलंबन योजना, पवनपुत्र योजना, मधुबनी योजना, निर्मित योजना, सहकार योजन, रफ्तार योजना, धमतरी योजना, न्याय योजना, सहारा योजना इत्यादि।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा भी शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनायें चलाई जा रही है। जिनका समाज पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते है। ये योजनायें निम्नलिखित है– गोकुल ग्राम प्रकल्प योजनाए, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, विवेकानंद समूह बीमा योजना, बाल शक्ति योजना, विजयाराजे जननी कल्याण बीमा योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ग्राम ज्योति योजना, सबला योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, पंच परमेश्वर योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, रुक जाना नहीं योजना इत्यादि। उपर्युक्त योजनाओं का अध्ययन करने के पश्चात इन योजनाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर के माध्यम से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों से साक्षात्कार करके पता करने की कोशिश करते है कि समाज पर इन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है।

संचालित ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं का विकास में योगदान का मूल्यांकन

मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित की जा रही ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का विकास में क्या योगदान रहा है। यह जानने लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न गॉवों व शहरों में ऑनलाइन सर्वेक्षण कार्य किया गया है, जिसमें 100 लोगों से कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे गये जिनके अधार पर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओ को धारातल पर परखने की कोशिश की गई है। ऑनलाइन सर्वेक्षण कार्य में जो परिणाम आये है उनका मूल्यॉकन निम्नलिखत है–

प्र. 01: आपके परिवार की प्रकृति क्या/कैसी है?

उ. 01: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 50.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति ''संयुक्त'' है। तथा वही 43.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति ''एंकाकी'' है। और वही 7.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति ''अन्य'' है।

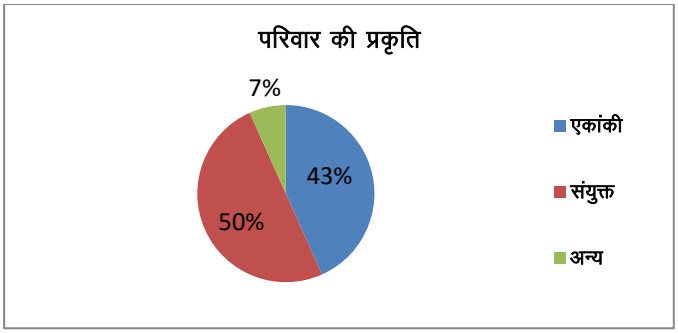

चित्र: 01

प्र. 02: आपके परिवार की ग्रामीण आवास की स्थिति कैसी है?

उ. 02: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 13.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की आवास की स्थिति में उनका घर ''कच्चा'' है। 54.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की आवास की स्थिति में उनका घर ''पक्का'' है। तथा वही 13.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की आवास की स्थिति में उनका घर '' सरकार द्वारा आवास योजना के अर्न्तगत'' का है। तथा वही 13.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की आवास की स्थिति में उनका घर ''किराये'' का है। वही 07 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की आवास की स्थिति में उनका घर ''रिश्तेदारो या सगेसम्बन्धियों'' का है।

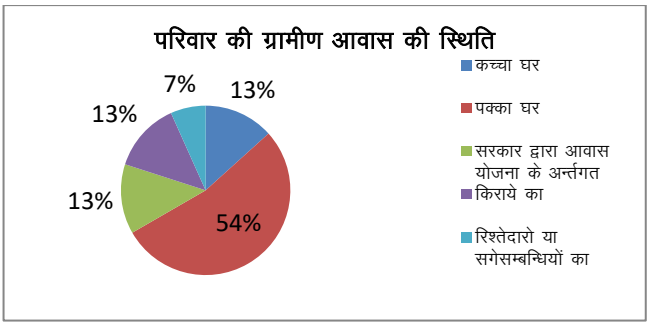

चित्र: 02

प्र. 03: क्या आपको शासकीय ग्रामीण योजनाओं के बारे मे कोई जानकारी है?

उ. 03: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''हॉ'' में उत्तर दिया गया। तथा वही 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''नही'' में उत्तर दिया गया। तथा वही 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा '' थोड़ी–बहुत'' में उत्तर दिया गया।

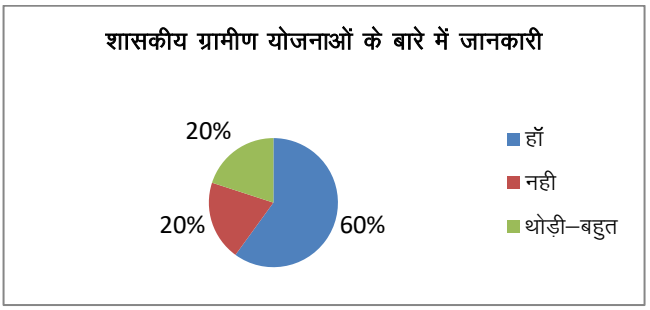

चित्र: 03

प्र. 04: आपको कौन सी शासकीय ग्रामीण योजनाओं के बारे मे जानकारी है?

उ. 04: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको ''आवास योजना'' की जानकारी है। 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको ''चिकित्सीय योजना'' की जानकारी है। 07 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको ''शैक्षिक योजना'' की जानकारी है। 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको ''स्वरोजगार योजना'' एवं अन्य योजना की जानकारी है। 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको ''उर्पयुक्त सभी'' योजनाओं की जानकारी है। और वही 07 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको ''किसी भी योजनाओं की जानकारी'' नही है।

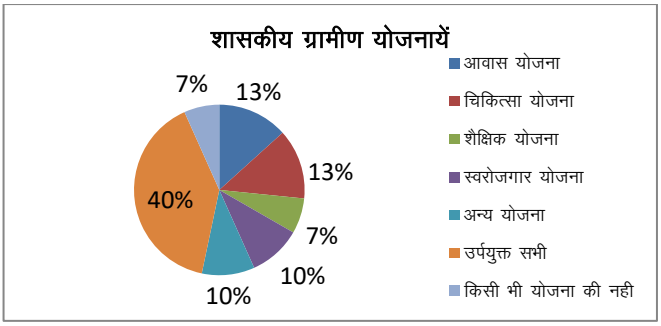

चित्र: 04

प्र. 05: आपको शासकीय ग्रामीण योजनाओं के बारे मे जानकारी कहॉ से मिलती है?

उ. 05: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको शासकीय योजनाओं की जानकारी ''शासकीय कर्मचारियों'' द्वारा मिली। 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको शासकीय योजनाओं की जानकारी ''एन.जी.ओ.'' द्वारा मिली। 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको शासकीय योजनाओं की जानकारी ''इन्टरनेट'' द्वारा मिली। 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको शासकीय योजनाओं की जानकारी ''जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा'' मिली। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको शासकीय योजनाओं की जानकारी ''अन्य प्रकार से'' मिली। 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको शासकीय योजनाओं की जानकारी ''किसी के द्वारा नही'' मिली।

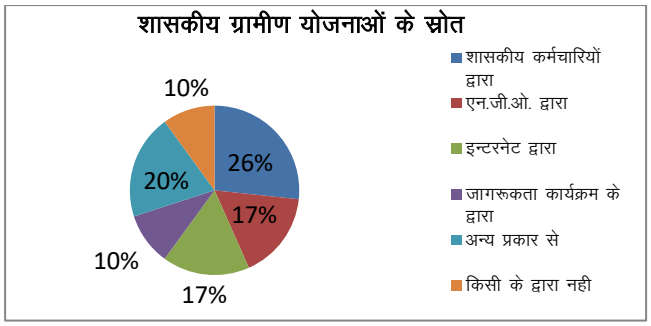

चित्र: 05

प्र. 06: आपने कोई शासकीय ग्रामीण योजना का लाभ लिया है?

उ. 06: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''हॉ'' में उत्तर दिया गया। वही 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''नही'' में उत्तर दिया गया। और वही 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''मुझे पता ही नही है'' में उत्तर दिया गया।

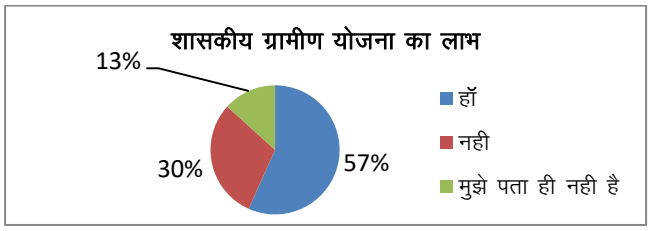

चित्र: 06

प्र. 07: आपके परिवार के किसी सदस्य ने शासकीय ग्रामीण योजना का लाभ लिया है?

उ. 07: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''हॉ'' में उत्तर दिया गया। वही 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''नही'' में उत्तर दिया गया। और वही 07 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''मुझे पता ही नही है'' में उत्तर दिया गया।

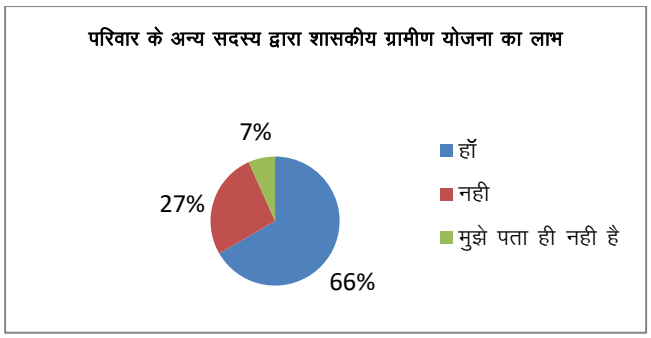

चित्र: 07

प्र. 08: क्या आप बता सकते है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में चलाई जा रही योजनाओं से समाज को लाभ होता है?

उ. 08: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''हॉ'' में उत्तर दिया गया। वही 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''नही'' में उत्तर दिया गया। और वही 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''थोड़ा बहुत'' में उत्तर दिया गया। और वही 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''कुछ लोगों को होता है और कुछ को नही'' में उत्तर दिया गया।

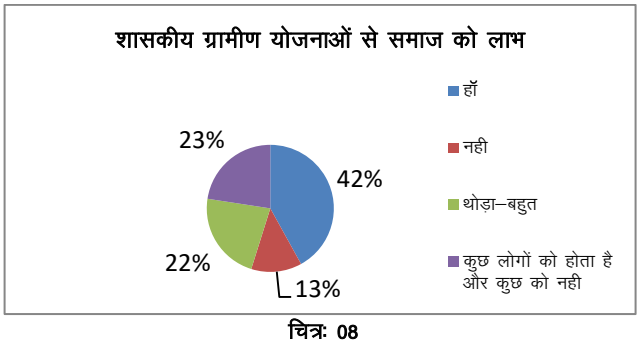

चित्र: 08

प्र. 09: क्या आप मानते है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है?

उ. 09: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''हॉ'' में उत्तर दिया गया। वही 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''नही'' में उत्तर दिया गया। और वही 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''थोड़ा बहुत'' में उत्तर दिया गया।

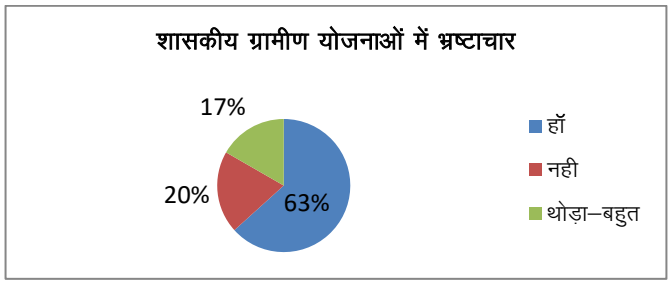

चित्र: 09

प्र. 10: आपको कोई शासकीय ग्रामीण योजना का लाभ भविष्य में मिलेगा तो लेना चाहोगे ?

उ. 09: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''हॉ'' में उत्तर दिया गया। वही 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''नही'' में उत्तर दिया गया। और वही 03 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''थोड़ा बहुत'' में उत्तर दिया गया।

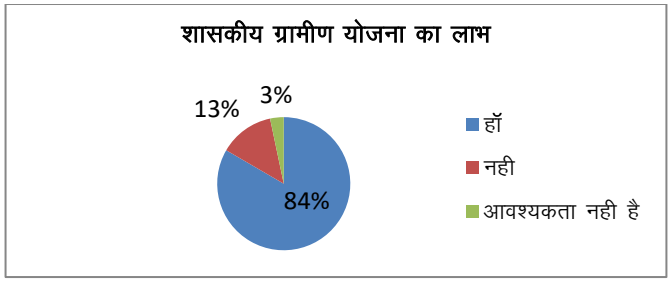

चित्र: 10

विवेचन एवं निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं का प्रभाव समाज पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनो प्रकार से पड़ता है। क्योकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी है वह अधिकतर अशिक्षा से ग्रसित होती है। अशिक्षित होने की बजह से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों को अक्सर योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी नही मिल पाती है। जिसके कारण वह प्रक्रिया को पूर्ण नही कर पाते है। वही जो लोग थोड़े से पढ़े–लिखे है। वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लेते है। अक्सर देखा गया है कि जो इन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुॅचाने का कार्य करते है वो ही भेदभाव कर देते है। जिससे जो पात्र व्यक्ति होते है या जिनको जरूरत होती है उनको इन योजनाओं का फायदा मिल ही नही पाता है। इस सम्बन्ध में सर्वे प्रश्न क्रमांक 09 का अवलोकन करने पर पाया कि 63 प्रतिशत लोगों का मानना है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है। पूर्ण रूपेण तो नही लेकिन 63 प्रतिशत बहुत होता है। और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं का दूसरा पहलू भी देखा जाए तो इन योजनाओं का पर्याप्त रूप से विज्ञापन ना होना भी एक बजह है जिससे लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। और आम जन इनका लाभ नहीं उठा पाते। अब यदि सरकार चाहे तो आधार कार्ड के माध्यम से उन लोगों को आसानी से चिन्हित किया जा सकता है जिनको इन योजनाओं की आवश्यकता है। जैसा कि सरकार द्वारा कोविड–19 के समय में किया गया और जिन लोगों को मदद की आवश्यकता थी उनको मदद पहुॅचाई गयी। कोविड–19 के समय में प्रक्रिया को सरल बना दिया गया था। जिससे पात्र व्यक्तियों को आसानी से इन योजनाओं का फायदा मिल सका। सरकारी योजनाओं को पाने के लिए जो प्रक्रिया है वह बहुत ही धीमी गति से होती है, या तो यूं कहें कि सरकार के पास इतने कर्मचारियों का अभाव है। अन्ततः हम कह सकते है कि शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन मानस तक पहुचाने के लिए समय के साथ बदलती परिस्थतियों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

सुझाव

1. मतदाता सूची व आधार कार्ड के अनुसार पात्र व्यक्तियों की सूची बनाकर अपडेट कर देना चाहिए।
2. सरकार द्वारा अपडेट किये गये लोगों को ही इनका फायदा मिले और जो लोग किसी कारण वश रह जाये तो उनके गॉव के पास की हेल्प सेन्टर बनाये जाने चाहिये।
3. हेल्प सेन्टरो की समय–समय पर मॉनीटरिंग करने के लिए अलग–अलग टीमों को गठित किया जाना चाहियें। जिससे हेल्प सेन्टरो के कर्मचारी व मॉनीटरिंग करने वाली टीमें आपस में न मिल सकें।
4. सरकार द्वारा ऐसी कमेटियों या समूहों को भी बनाया जाना चाहिये जो समय–समय पर जाकर कुछ अंतरालों में गांवो, नगरों का सर्वेक्षण करें और पात्र व्यक्तियों को ढूंढ करके उनकी सूची बनाएं और उन्हें लाभान्वित करें। और जो अपात्र होते जाये उनको सूची से हटाया जायें।

सन्दर्भ सूची

1. मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास विभागः https://nregsmp.org/rddmp_new/index.htm
2. गोविन्द आर्यः मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजनाः प्रकाशित दिनॉक 25 जून 2020, अवलोन दिनॉक 02 दिसम्बर 2021: https://kaisekarehelp.com/mp-vidhwa-punar-vivah-yojana/
3. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः जिला गवालियरः अवलोन दिनॉक 05 दिसम्बर 2021: https://gwalior.nic.in/en/scheme/mukhyamantri-swarojgar-yojana/
4. लाड़ली लक्ष्मी योजनाः https://ladlilaxmi.mp.gov.in/

****